(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. जे. कुरियन): (क) जी, नहीं। लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले कुटीर तथा कृषि उद्योगों के लिए सरकार से लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। लघु उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले इन उद्योगों का पंजीकर कराना भी अनिवार्य नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

2406. [*Transferred to the 17th March, 1992*].

Salt produced in Gujarat

2407. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is fact that 60 per cent of the country's salt is produced by Gujarat;

(b) whether any memorandum from Salt Industry has recently been received for upgrading the post of Deputy Salt Commissioner at Ahmedabad; and

(c) if so, what action has been taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) It has not been found necessary to upgrade the post of Deputy Salt Commissioner at Ahmedabad.

Month-wise indicates of industrial production

2408. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what has been the monthwise indices of industrial production during April-December, 1991;

(b) how these compare with indices during the same period of 1990;

(c) the causes for recessionary trends; and

(d) the steps taken to boost effective demand?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI P. J. KURIEN): (a) and (b) A Statement is enclosed. (*See* below).

(c) There are various factors like import restrictions, especially for capital goods, raw-materials and components owing to foreign exchange constraints, credit squeeze, a slump in demand etc.

(d) A number of measures announced in the Union Budget for 1992-93 such as partial convertibility of the rupee, reduction of duties in capital goods and elimination of import licensing except in the case of a small negative list, reducton in statutory liquidity ratio, reduction in interest rate etc., are designed to boost effective demand.

Statement

Index of Industrial Production

(*Base*: 1980-81=100)

Month	1990-91	1991-92	%Change
April	197·2	195·4	—0·9
May	201.6	159.7	—2.9

Month	1990-91	1991-92	%Change
June	203·4	197·3	—3.0
July	201·9	205·3	1·7
August	201·0	199·1	—0·9
September	198·1	199·5	0·7
October	200·3	199·4	—0·4
November	204·6	201·5	—1·5
April—November	201·0	199·2	—0·9

Source : C.S.O.

N. B. The figures for December 1991 will be available only by the end of March 1992

उत्तर प्रदेश में उद्योग रहित जिले

2409. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के कौन-कौन से जिले को उद्योग रहित जिलों की सूची में शामिल किया गया है :

(ख) क्या उन जिलों में औद्योगिक एककों की स्थापना के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो इन औद्योगिक एककों की स्थापना कब तक कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० जे० कुरियन) : (क) उत्तर प्रदेश में बांदा, चमोली, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन, जोनपुर, पौढ़ी गढ़वाल, सुनालपुर, टिहरी गढ़वाल, उत्तर काशी और कानपुर देहात "उद्योग रहित जिल" घोषित किए गए हैं।

(ख) से (घ) किसी क्षेत्र का औद्योगीकरण करना मुख्यतया संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होता है। जहां कहीं संभव होता है, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगीकरण के लिए सरकार ने एक विकास केन्द्र योजना आरंभ की है जिसके तहत उत्तर प्रदेश को आठ विकास केन्द्र आबंटित किए गए हैं, झांसी, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, इटावा, बुलंदशहर, जौनपुर, गोरखपुर और पौढ़ी गढ़वाल जिलों में एक-एक केन्द्र है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो विकास केन्द्र स्थापित किए जायेंगे, उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं मुहैया करायी जायेंगी।

2410. [*Transferred to the 23rd March*, 1992].

Funds for growth centres

2411. SHRIMATI MANORMA PANDEY: Will the PRIME MINISTER be pleased to refer to the reply to Unstarred Question 3206 given in the Rajya Sabha on the 19th December, 1991 and state:

(a) whether Government have released funds for developing and providing infrastructural facilities to various growth centres in the country; if so, what are the details thereof, centre-wise;

(b) whether it is a fact that no infrastructural facilities have yet been developed since June 1988, in